

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 353-पीबीआर/2012 - विरुद्ध आदेश
दिनांक 31-1-12 - पारित द्वारा - अपर कलेक्टर, विदिशा -
प्रकरण क्रमांक 217/10-11 निगरानी

आजाद सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह
ग्राम ओलीजा तहसील ग्यारसपुर
जिला विदिशा मध्य प्रदेश

---आवेदक

विरुद्ध

श्रीमती राधिका सिंह पत्नि परमेश्वरनाथ
पुत्री पतिराम निवासी नई बस्ती चांदपुर
मौजा सिंगड़ी तहसील बासडीह, बलिया (उत्तर प्रदेश)

---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस०के०अवस्थी)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री आर०डी०शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 6-07,-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक
217/10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31 जनवरी,
2012 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा
50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार
ग्यारसपुर के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की
धारा 110 के अंतर्गत आवेदन दिनांक 29-1-10 प्रस्तुत कर
आग्रह किया कि ग्राम ओलीजा स्थित भूमि सर्वे नंबर 568/2
रकबा 2.00 हेक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया
गया है) पतिराम पुत्र बलदेवसिंह के नाम भूमिस्वामी के रूप में

E/19

Om

दर्ज है। पतिराम की मृत्यु 20-8-10 को हो चुकी है। पतिराम द्वारा दिनांक 20-8-2007 को एक बसीयतनामा उसके नाम निष्पादित किया है। बसीयत के आधार पर नामान्तरण किया जाय। तहसीलदार ग्यारसपुर ने प्रकरण क्रमांक 41-अ-6/ 2009-10 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक की सुनवाई कर आदेश दिनांक 6-3-2010 पारित किया एवं आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर ने प्रकरण क्रमांक 47/09-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-6-2010 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार ग्यारसपुर का आदेश दिनांक 6-3-2010 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर, विदिशा के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 217/10-11 में पारित आदेश दिनांक 31-1-12 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।


3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया आवेदक ने पतिराम पुत्र बल्देवसिंह के नाम की वादग्रस्त भूमि पर बसीयत के आधार पर नामान्तरण चाहा है। बसीयत की मूल प्रति तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 41-अ-6/ 2009-10 में पृष्ठ 4 पर संलग्न है जो श्री पुरुषोत्तम कुशवाह एडवोकेट द्वारा तस्दीक है एवं बसीयत पर पतिराम का निशानी अँगूठा लगा है। बसीयत में लिखवाया गया है कि बसीयतकर्ता के कोई संतान नहीं

है जबकि बसीयतकर्ता की अनावेदक पुत्री है जिसे तहसील न्यायालय में आवेदक ने पक्षकार नहीं बनाया है तथा तहसीलदार ने भी पटवारी से अथवा ग्रामीणों से मृतक पतिराम के वारिसान की जानकारी प्राप्त नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय में पतिराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत हुआ है जो उत्तर प्रदेश का है। मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार पतिराम 4-1-10 को मरा है जबकि आवेदक ने पतिराम की मृत्यु 20-8-10 को होना बताई है। अनावेदक पतिराम की पुत्री है और उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना तहसीलदार ने एकपक्षीय आदेश पारित किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर ने आदेश दिनांक 29-6-10 से तहसीलदार के त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त करने में एवं हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने में त्रुटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर, विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 217/10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2012 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एवं अपर कलेक्टर, विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 217/10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2012 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

B
1/14


(एम0के0सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर